इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (मरुगंगा)

डॉ. महेन्द्र कुमार सुनार

प्रस्तावना :

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ की कृषि की स्थिति दयनीय बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ वर्षा की अनियमितता अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता सदैव बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूगर्भित जल के स्त्रोत घटता जा रहा है। कुओं, तालाबों, बावडियों, टांकों का पानी निरन्तर सूखता जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या लगभग बनी रहती है।

राजस्थान का पश्चिमी भाग जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल (3.42 लाख वर्ग किमी) का 60 प्रतिशत भाग है, जिसमें यह मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे विश्व में थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जहाँ सिंचाई तो दूर की बात है, वहाँ पेयजल की भारी किल्लत रहती है। जहाँ दूर–दूर तक बालू रेत (टीलों) का अथाह सागर नजर आता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को हराभरा करने, पेयजल की पर्याप्त सुविधा करने, कृषि के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण एवं भागीरथी प्रयास की परिकल्पना की गई, कि हिमालय से बहने वाली नदियों का पानी इस क्षेत्र में पहुँचा दिया जावे, तो यह मरुभूमि सोना उगलने लग जावेगी।

बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह जी ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर में सतलज नदी के पानी को प्रयुक्त करके गंगानगर के पश्चिमी सीमावर्ती भाग में पेयजल व सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। गंग नहर से प्रेरणा लेकर बीकानेर रियासत के तत्कालीन राज्य इंजीनियर कंवर सेन, जिन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सतलज–व्यास नदी पर पंजाब के फिरोजपुर में 'हरीके बेराज' बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। भारत–पाक नदी जल बंटवारे के अन्तर्गत व्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपभोग में लेने की व्यवस्था से यह आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बनाकर इनके जल का उपयोग किया जाए। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार करवाई और सर्वप्रथम 1952 में 'हरिके बैराज' का निर्माण फिरोजपुर (पंजाब) के निकट सतलज–व्यास नदियों के संगम पर कराया गया, इसी से इन्दिरा गांधी नहर निकाली गई। राजस्थान सरकार द्वारा 1954–55 में एक विस्तृत सर्वेक्षण करवा कर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की रिपोर्ट तैयार करवायी, जिस पर लगभग 66 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट को योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। योजना आयोग ने गहन अध्ययन करके इस प्रारुप पर अपनी स्वीकृति दे दी। अन्ततः 31 मार्च 1958 को तत्कालीन भारत के गृहमंत्री स्व. श्री गोविन्द बल्लभ पंत से इस नहर के निर्माण कार्य का श्रीगणेश किया।

इन्दिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमति इन्दिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात् 2 नवम्बर 1984 को इसका नाम 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना' कर दिया गया। इन्दिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा, भागीरथी, देवगंगा राज्य की जीवन रेखा (Life Line) आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। इस नहर ने राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की कायाकल्प ही कर दिया। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एक सामान्य सिंचाई परियोजना ही नहीं बल्कि यह आकार, लम्बाई, क्षमता, सिंचाई क्षेत्र, निर्माण सामग्री की मांग व जनशक्ति की दृष्टि से विश्व की वृहदतम परियोजनाओं में से एक है। यह एशिया महाद्वीप की पहली मानव निर्मित सबसे विशाल एक मात्र नहर है। थार के मरुस्थल क्षेत्र में सिंचाई व पीने के पानी को सुलभ कराने वाली इन्दिरा गांधी नहर को यद्यपि नहर का नाम दिया गया किन्तु

इसकी विशालता एवं महत्ता को देखते हुए, इस नहर को इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बहने वाली नदी सरस्वती नदी के पुनः अवतरण की संज्ञा दी जा सकती है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रकृति की असीम विषमताओं से मनुष्य के अदम्य साहस पूर्ण संघर्ष से उत्पन्न सृजनात्मक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना से पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि, दूरस्थ हिमालय की व्यास व सतलज नदियों के जल से सिंचित होकर जीवंत हुई है तथा करोड़ों निवासियों को पेयजल उपलब्ध हुआ है। इन्दिरा गांधी नहर पंजाब के हरिके वैराज से निकलकर बाड़मेर के गडरारोड़ तक जाती है। जिसे जीरो पाइन्ट कहा जाता है। सुविधा एवं सुगमता की दृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर को दो भागों में बांटा गया।

प्रथम इन्दिरा गांधी फीडर और द्वितीय मुख्य नहर। इन्दिरा गांधी नहर की कुल लम्बाई 649 कि.मी. है। इन्दिरा गांधी फीडर की लम्बाई 204 कि.मी. (जिसमें प्रथम 169 किमी पंजाब, 14 किमी हरियाणा व शेष 21 किमी राजस्थान में है) तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 कि.मी. है। नहर का जो भाग फीडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी भूतल से चौड़ाई 37 मीटर, सतह चौड़ाई 65 मीटर तथा गहराई 6.5 मीटर के लगभग है। नहर का निर्माण कार्य दो चरणों में विभक्त किया गया है – प्रथम चरण में इस परियोजना के अन्तर्गत 204 कि.मी. लम्बी फीडर तथा उससे आगे 189 किमी. लम्बी मुख्य नहर और 3136 कि.मी. लम्बी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा गया जिस पर जो लगभग 343 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है। उससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है।

द्वितीय चरण में परियोजना की लागत 2452 करोड़ रूपये आंकी गई थी। इसमें 256 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर और लगभग 5115 कि.मी. लम्बी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण का लक्ष्य रखा गया अब वह भी पूर्ण हो चुका है, और जैसलमेर जिले के सुदूर गांव मोहनगढ़ तक पानी पहुँचा दिया गया है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 10 शाखाऐं व 7 लिफ्ट नहरें बनायी गई। लिफ्ट नहरें निम्न हैं – डॉ. कर्णी सिंह लिफ्ट नहर (पूर्व में कोलायत लिफ्ट नहर), गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (पूर्व में फलौदी लिफ्ट नहर), कंवर सेन लिफ्ट नहर (पूर्व में लूणकरणसर लिफ्ट नहर), जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर (पूर्व में पोखरण लिफ्ट नहर), वीर तेजाजी लिफ्ट नहर (पूर्व में बांगड सर लिफ्ट नहर), पन्नालाल बारुपास लिफ्ट नहर (पूर्व में गजनेर लिफ्ट नहर), चौधरी कुम्भाराय आर्य लिफ्ट नहर (पूर्व में साहवा लिफ्ट नहर) हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्य पर आरम्भ से मार्च 2016, तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, द्वारा 4679.21 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें प्रथम चरण में 573.62 करोड़ रूपये एवं द्वितीय चरण में 4105.59 करोड़ रुपये। वर्ष 2015–2016 में नहर के पानी से 15.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई। नहर के पूर्ण हो जाने से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चुरू जिलों को सिंचाई व पेयजल का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसके साथ ही झुन्झुनूं, सीकर, नागौर, तथा बाड़मेर जिलों को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाये जाने की योजना प्रस्तावित है। नहर से पानी की पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता में, रोजगार के साधनों में, औद्योगिक विकास आधारभूत सुविधाओं में लोगों के जीवन स्तर में सघन वृक्षारोपण में, मरुस्थल विस्तार में कमी आयी, चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि हुई। सूखे व अकाल की समस्या से इस क्षेत्र को मुक्ति मिली है। नहर के कई स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाऐं लगाई गई है। इसके साथ ही नहर से सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना को भी पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह नहर पाकिस्तान से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवायी जाती थी उसे रोकने में कामयाब रही है। अन्ततः कहा जा सकता है, कि राजस्थान के चहुँमुखी विकास में इन्दिरा गांधी नहर (मरुगंगा) एक वरदान साबित हुई है।

विभागाध्यक्ष

आर्थिक एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग

अग्रवाल पी.जी. कॉलेज, जयपुर